दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स झारखंड

फरवरी 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

झारखंड **3**

- बोकारो के 3 छात्रों के प्रोजेक्ट इंस्पायर अवॉर्ड के लिये चयनित 3
- झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की 58 सड़कों और 26 पुलों को केंद्र से मिली स्वीकृति 3
- नीलांचल इस्पात निगम का अधिग्रहण करेगी टाटा स्टील 4
- झारखंड हाइकोर्ट के जज बनेंगे प्रदीप श्रीवास्तव 4
- खान एवं भूतत्त्व विभाग ने इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू किया 5
- झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14वीं बैठक 5
- 'पोस्ट काड्र्स फ्रॉम झारखंड' डॉक्यूमेंट्री 6
- एससी-एसटी की सूची में बदलाव हेतु संशोधन विधेयक 6
- अटल पेंशन योजना में झारखंड के 16 ज़िलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन 6
- थर्मोकोल पर प्रतिबंध 7
- जनजातीय कल्याण से संबंधित मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 7
- एशियन वाटर बड्र्स सेंसस 2022 8
- वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 8
- क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिये ज़िला एवं राज्यस्तरीय प्रतियोगिता से चयनित होंगे प्रतिभाशाली बच्चे 9
- जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की नई सूची जारी 9
- एकीकृत कृषि प्रणाली में पशुधन को शामिल करना अत्यंत उपयोगी 9
- दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी 10
- राज्य में खुला पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र 10
- तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड विनर 'गुनी गाँव' 11

नोट :

झारखंड

बोकारो के 3 छात्रों के प्रोजेक्ट इंस्पायर अवॉर्ड के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

- 31 जनवरी, 2022 को डीपीएस बोकारो के तीन छात्र कक्षा IX के उत्कर्ष राज एवं अभिनीत शरण तथा कक्षा VIII की अंजलि कुमारी को INSPIRE अवार्ड - MANAK (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज) के लिये चयनित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- ये तीनों विद्यार्थी जिला शिक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली जिलास्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में अपने विद्यालय डीपीएस बोकारो का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- गौरतलब है कि INSPIRE अवार्ड - MANAK (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन - इंडिया (NIF) के साथ निष्पादित किया जाता है।
- इस पुरस्कार का उद्देश्य कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों में रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोगों में निहित दस लाख मूल विचारों/नवाचारों को लक्षित करना है।
- इसमें चयनित प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपए की राशि प्राप्त होने के साथ वे जिलास्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। आगे छात्रों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अंत में एक हजार छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
- एनआईएफ द्वारा साठ नवीन परियोजनाओं को पूरी तरह से इन्क्यूबेशन सुविधा (पेटेंट फाइलिंग, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास में मूल्यवर्धन आदि) प्रदान की जाएगी और इसे वार्षिक नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव (FINE) में प्रदर्शित किया जाएगा।

झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की 58 सड़कों और 26 पुलों को केंद्र से मिली स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

- 31 जनवरी, 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये 361 किमी. सड़क योजना और 26 पुल योजनाओं को स्वीकृति दे दी। इसके तहत राज्य में कुल 58 सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में झारखंड की ओर से शामिल हुए एक अधिकारी ने बताया कि ये सड़कें अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये केंद्र के प्रोजेक्ट आरसीपीएलडब्ल्यूई योजना के दूसरे फेज के तहत बनाई जानी हैं। झारखंड सरकार की ओर से योजनाओं की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पेश की गई, जिसे मंजूरी दे दी गई।
- कुल 58 ग्रामीण सड़कों व 26 पुलों के निर्माण के लिये केंद्र सरकार 188 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करेगी, वहीं झारखंड सरकार 127 करोड़ रुपए देगी।
- इसके अलावा केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 71 किमी. की सड़क योजनाओं को भी स्वीकृति दे दी है। इसके लिये अभी केंद्र के स्तर पर बैठक होगी। दो-तीन चरणों की बैठक में सहमति बनने के बाद इस पर अंतिम रूप से सहमति दी जाएगी।
- उग्रवाद प्रभावित गढ़वा जिले के बड़गड एवं रमकंडा में आरसीपीएलडब्ल्यूइए से नौ सड़कें बनेंगी। कुल 78 किमी. लंबी इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- उल्लेखनीय है कि अक्तूबर 2021 में राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस योजना के पहले चरण के तहत 125 सड़कों और 71 पुलों के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई थी। इन योजनाओं पर 765 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

नीलांचल इस्पात निगम का अधिग्रहण करेगी टाटा स्टील

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को 12,100 करोड़ रुपए में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अधिकृत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे, ने 12,100 करोड़ रुपए की बोली लगाने के बाद टीएसपीएल को नीलांचल इस्पात का मालिकाना हक सौंपने की मंजूरी दी।
- नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिये तीन कंपनियों ने बोली लगाई थी जिसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के अलावा जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, नलवा स्टील पावर लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्कील शामिल थी। लेकिन सबसे ज्यादा बोली लगाने के चलते यह कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को सौंपी गई।
- एनआईएनएल सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों एमएमटीसी (MMTC) लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), भेल (BHEL) और मेकॉन (MECON) लिमिटेड समेत ओडिशा सरकार की दो कंपनियों OMC और IPICOL का संयुत्त उपक्रम है। नीलांचल इस्पात लिमिटेड में इन सभी कंपनियों की 93.71 फीसदी हिस्सेदारी है।
- नीलांचल इस्पात का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ओडिशा के कलिंगनगर में स्थित है जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 11 लाख टन है। कंपनी भारी घाटे में चल रही है और 30 मार्च, 2020 से बंद है।
- एनआईएनएल पर पिछले साल 31 मार्च को 6,600 करोड़ से अधिक का कर्ज था। इसमें प्रमोटरों 4,116 करोड़ रुपए, बैंकों का 1,741 करोड़ तथा अन्य लेनदारों और कर्मचारियों का बकाया शामिल है। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की निवल संपत्ति (negative networth) 3,487 करोड़ और संचित घाटा (accumulated losses) लगभग 4,228 करोड़ रुपए है।
- उल्लेखनीय है कि मौजूदा केंद्रीय सरकार में एनआईएनएल का प्राइवेटाइजेशन दूसरा सफल प्राइवेटाइजेशन है। इस लिस्ट में पहली कंपनी एयर इंडिया है जिसे हाल में टाटा ग्रुप ने खरीदा है। टाटा ने एयर इंडिया की खरीद के लिये 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई और अपने नाम किया।

झारखंड हाइकोर्ट के जज बनेंगे प्रदीप श्रीवास्तव

चर्चा में क्यों ?

- 1 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड हाईकोर्ट का जज बनाने की अनुशंसा की।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उपरोक्त सिफारिश को दोहराया है। कॉलेजियम ने पिछले वर्ष 1 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त न्यायिक अधिकारी के नाम को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया था।
- विदित हो कि हाल ही में झारखंड न्यायिक सेवा के चार अधिकारियों को प्रोन्नति देकर झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था।
- वर्तमान में प्रदीप श्रीवास्तव बोकारो के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक एंड सेशन जज के पद पर पदस्थापित हैं।
- झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 25 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन सहित 20 न्यायाधीश कार्यरत् हैं।

खान एवं भूतत्त्व विभाग ने इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू किया

चर्चा में क्यों ?

- 3 फरवरी, 2022 को झारखंड के खान एवं भूतत्त्व विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिये इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (आईएफओआरईएसटी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू के तहत आईएफओआरईएसटी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बेहतरी के लिये जानकारी और प्रशिक्षण मुहैया कराएगा।
- गौरतलब है कि एमओयू के लिये राज्य मंत्रिमंडल ने इस साल 19 जनवरी को ही अपनी सहमति दे दी थी। एमओयू दो वर्षों के लिये हुआ है, लेकिन आपसी समझ से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।
- खान एवं भूतत्त्व सचिव पूजा सिंघल की मौजूदगी में इस एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से खान निदेशक अमित कुमार और आईएफओआरईएसटी के सीईओ चंद्रभूषण ने हस्ताक्षर किये।
- एमओयू के अनुसार आईएफओआरईएसटी डीएमएफ को पॉलिसी, प्लानिंग और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा, ताकि डीएमएफ के कार्यों में गुणात्मक और फलदायी परिणाम मिल सके।
- आईएफओआरईएसटी खान विभाग को भी खनन क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय पुनर्वास में सहयोग करेगा। इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।

झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

- 3 फरवरी, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन्य प्राणी आश्रयणियों के प्रबंधन योजना, झारखंड वन्य प्राणी नीति का निर्माण सहित कुल नौ एजेंडों पर चर्चा की।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में वन्य प्राणी आश्रयणियों के प्रबंधन योजना, झारखंड वन्य प्राणी नीति का निर्माण, राज्य के वन्य प्राणी अभयारण्यों के अंदर अवस्थित गाँवों के ग्रामीणों की स्वास्थ्य समस्याओं के निदान, राँची-जमशेदपुर NH के किनारे वृहत् पौधारोपण, साहिबगंज में फॉसिल पार्क का निर्माण कार्य समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
- मुख्यमंत्री ने पलामू टाइगर रिजर्व, लावालौंग वन्य प्राणी आश्रयणी, गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयणी समेत वनभूमि से होकर गुजरने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, पुल निर्माण में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करने का आदेश दिया।
- उन्होंने कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयणी से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण हेतु एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुपालन में पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न उपयुक्त स्थानों पर शिविर लगाने का प्रावधान पर्यटन नीति के तहत किया गया है। इसके लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पर्यटन विभाग पर्यटकों के लिये वन्यजीव पार्कों/चिड़ियाघरों, बर्ड वाच टावर और अन्य उपयोगी सेवाओं के विकास तथा सुधार के लिये वन और पर्यावरण विभाग के साथ कार्य करेगा। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन के अभिन्न अंग के रूप में एकीकृत होंगे।
- मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में फॉसिल पार्क के निर्माण को लेकर वन विभाग को विशेष निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि साहिबगंज में फॉसिल पार्क निर्माणाधीन है। इसके निर्माण के बाद पर्यटक सैकड़ों वर्ष पूर्व के जीवाश्म देख सकेंगे। इसके साथ ही वन विभाग राजमहल की पहाड़ियों समेत अन्य स्थानों पर फॉसिल पार्क की संभावनाओं को तलाश रहा है।
- मुख्यमंत्री ने वन्य जीव, खासकर हाथी कॉरिडोर पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि इनके लिये अंडरपास का निर्माण बेहतर ढंग से करवाएँ, ताकि वन्यजीवों को सड़क पार करने में सुविधा हो सके।

'पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम झारखंड' डॉक्यूमेंट्री

चर्चा में क्यों ?

- 4 फरवरी, 2022 को नेशनल ज्योग्राफिक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष 'पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम झारखंड' नाम से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री का प्रेजेंटेशन दिया।

प्रमुख बिंदु

- इस डॉक्यूमेंट्री में चार अलग-अलग फिल्में होंगी। पहली फिल्म में बेतला-मैक्लुस्कीगंज-नेतरहाट और आस-पास के क्षेत्र, दूसरी फिल्म गिरिडीह- देवघर -मलूटी और आस-पास के क्षेत्र, तीसरी फिल्म में जमशेदपुर- खूंटी और सरायकेला और आस-पास के क्षेत्र तथा चौथी फिल्म राँची-हज़ारीबाग और आस-पास के क्षेत्रों में अवस्थित पर्यटक स्थलों पर आधारित होगी।
- मुख्यमंत्री ने नेशनल ज्योग्राफिक के प्रतिनिधियों को अपने कुछ सुझाव भी दिये। जैसे झारखंड पर्यटन पर कॉफी टेबल बुक तैयार करना, ताकि इसके माध्यम से झारखंड पर्यटन से जुड़ी जानकारी लोगों से साझा की जा सके।
- झारखंड खान और खनिज के अलावा यहाँ के लोगों खासकर आदिवासियों और उनकी परंपरा, रीति-रिवाज, कला-संस्कृति, खानपान और रहन-सहन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर, पुरातात्त्विक अवशेष, हेरिटेज, मेगालिथ, अध्यात्म और एडवेंचर्स स्पोर्ट्स आदि के क्षेत्र में काफी समृद्ध है। जैसे- हजारीबाग के इस्को गाँव में मिली रॉक पेंटिंग दो से पाँच हज़ार ईसा पूर्व की बताई जाती है वहीं गुमला ज़िले के कोजेंगा के जंगल से हज़ारों साल पुरानी एक रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है।

एससी-एसटी की सूची में बदलाव हेतु संशोधन विधेयक

चर्चा में क्यों ?

- 7 फरवरी, 2022 को जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव करने वाला संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक के अनुसार झारखंड के भोगता समुदाय के साथ तमरिया/तमड़िया, पुरान, देशवारी, गंझू, दौलतबंदी (द्वालबंदी), पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी (खेरी) को भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल किया जाएगा।
- भोगता सहित अन्य जातियों के एससी से एसटी में आने से उन्हें बड़े आरक्षण के दायरे में शामिल होने का लाभ मिलेगा। राज्य में अभी एससी के लिये 10% और एसटी के लिये 26% आरक्षण है। इस कारण अतिरिक्त आरक्षण से लाभान्वित हो सकेंगे।
- तमरिया/तमाड़ को मुंडा की श्रेणी में सूचीबद्ध करने के लिये जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) ने वर्ष 2002 में अनुशंसा की थी। वहीं पुरान को एसटी में शामिल करने की अनुशंसा 1993 में जनजातीय शोध संस्थान ने की थी।
- उल्लेखनीय है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने भोगता जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से निकालकर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की थी।

अटल पेंशन योजना में झारखंड के 16 ज़िलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

- 8 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में बेहतर कार्य करने वाले झारखंड के 16 ज़िलों के एलडीएम को पेंशन निधि विनियामक, विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और एसएलबीसी के सहयोग से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पीएफआरडीए द्वारा झारखंड राज्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 1,95,220 नामांकन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध उपलब्धि 2,18,516 रही, जो कि लक्ष्य का 112 प्रतिशत है।
- इसके अलावा छह बैंकों- एसबीआई (198 प्रतिशत), बीओआई (147 प्रतिशत), झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (121 प्रतिशत), बैंक ऑफ बड़ौदा (108 प्रतिशत), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (104 प्रतिशत) एवं साउथ इंडियन बैंक (140 प्रतिशत) को भी एपीवाई के तहत नामांकन में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिये सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि अटल पेंशन योजना मई 2015 में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- इसमें 18-40 वर्ष के बीच की आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करती है।

थर्मोकोल पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

- 9 फरवरी, 2022 को झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ए.के. रस्तोगी ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई, 2022 से थर्मोकोल और प्लास्टिक से जुड़े सामान प्रतिबंधित रहेंगे।

प्रमुख बिंदु

- रस्तोगी ने बताया कि बोर्ड इसके लिये पहले ही निर्देश दे चुका है, ऐसे में इन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
- थर्मोकोल का वैज्ञानिक नाम Polystyrene है, पॉलीस्टाइरीन एक सिंथेटिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन बहुलक है, जिसे स्टाइरीन मोनोमर से बनाया जाता है।
- यह एक प्रकार का प्लास्टिक है, जिसको फूड पैकेजिंग, फोम की प्लेट्स, गिलास आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
- थर्मोप्लास्टिक बहुलक के रूप में, पॉलीस्टाइरीन कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है, लेकिन लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म होने पर तरल में परिवर्तित हो जाता है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के अनुसार पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन सहित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित होगा।

जनजातीय कल्याण से संबंधित मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 10 फरवरी, 2022 को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में जनजातीय कल्याण से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत Bharti Institute of Public - Indian School of Business (BIPP-ISB) के मनोनयन तथा त्रिपक्षीय MoU की स्वीकृति दी गई।
- जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र (मांझी हाउस), मानकी मुंडा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकड़िया हाउस निर्माण योजना का नाम परिवर्तित कर 'आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र/मांझी भवन, मानकी मुंडा भवन, पड़हा भवन, परगना भवन, धुमकड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण तथा मांझी थान शेड निर्माण योजना'करने एवं योजना की रूपरेखा तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

- संचालित 'सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना' के अंतर्गत लाभुक परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किये जाने हेतु जन- वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र 1/- रुपए की दर से डीलर कमीशन की स्वीकृति दी गई।
- इसके अतिरिक्त झारखंड पर्यटन नीति, 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति एवं झारखंड मुंसिपल पार्क मेंटीनेंस पॉलिसी,2021 की स्वीकृति दी गई।
- फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिये राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों एवं इच्छुक किसानों/किसानों के समूह की भूमि मंत कृषक पाठशाला तथा परिधि में अवस्थित राजस्व ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना'के क्रियान्वयन हेतु 61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।

एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस 2022

चर्चा में क्यों ?

- 12 फरवरी, 2022 को लातेहार ज़िले के ललमटिया डैम में झारखंड वन विभाग द्वारा तथा खूंटी के कर्रा स्थित लतरातू डैम में वेटलैंड इंटरनेशनल की सहभागिता से झारखंड जैव विविधता पर्षद द्वारा एशियन वाटरबर्ड सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना की गई।

प्रमुख बिंदु

- गणना के दौरान कॉमन किंगफिशर, रेड नेप्ड आईबिस, ओपन बिल स्टॉर्क, कॉमन कॉन्मोरेंट आदि प्रजातियाँ पाई गईं।
- गौरतलब है कि ठंड के मौसम में विभिन्न प्रजाति के प्रवासी पक्षी लातेहार ज़िला के जलाशयों को अपना आश्रय बनाते हैं।
- इस अवसर पर लालमटिया डैम में बर्ड वाचिंग टावर बनाने तथा इको टूरिज्म को विकसित करने पर चर्चा की गई। साथ ही लालमटिया डैम के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण एवं लालमटिया डैम में कैफेटेरिया निर्माण हेतु स्थल का अवलोकन किया गया।
- लातेहार ज़िला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिये प्रसिद्ध है जैसे कांती झरना, इंद्रा जल झरना आदि।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022

चर्चा में क्यों ?

- 14 फरवरी, 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह का औपचारिक उद्घाटन झारखंड में आरबीआई, राँची मुख्यालय के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा द्वारा किया गया।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिये 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह (FLW) आयोजित कर रहा है।
- इस वर्ष के वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय 'गो डिजिटल, गो सिक्योर' है, जो 14 फरवरी से 18 फरवरी तक मनाया जाएगा।
- वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान आरबीआई तीन संदेश- डिजिटल लेन-देन की सुविधा, डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा प्रसारित करेगा।
- RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिये कुछ अन्य उपाय भी किये गए हैं, जैसे-
  - भारतीय रिज़र्व बैंक ने FAME (वित्तीय जागरूकता संदेश) पुस्तिका का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसका उद्देश्य आम जनता को बुनियादी वित्तीय साक्षरता संदेश प्रदान करना है।
  - वित्तीय साक्षरता से संबंधित विषयों पर आम जनता के हित के लिये ऑडियो विजुअल तैयार किये गए हैं। ये ऑडियो विजुअल 'बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी', 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' और 'गोइंग डिजिटल' पर हैं।

क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिये ज़िला एवं राज्यस्तरीय प्रतियोगिता से चयनित होंगे प्रतिभाशाली बच्चे

चर्चा में क्यों ?

- 17 फरवरी, 2022 को झारखंड के खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा राज्य के समस्त ज़िला खेल पदाधिकारियों को कीड़ा प्रशिक्षण के लिये ज़िला एवं राज्यस्तरीय चयन प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के विभिन्न ज़िलों में संचालित आवासीय (हॉकी एवं तीरंदाज़ी को छोड़कर) एवं डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षुओं के चयन के लिये प्रतिभा चयन प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन होगा। यह आयोजन ज़िला से लेकर राज्यस्तर तक किया जाएगा।
- चयन प्रतियोगिता के तहत ज़िलास्तरीय प्रतियोगिता ज़िला मुख्यालय में 21 से 24 फरवरी 2022 तक एवं राज्यस्तरीय प्रतियोगियाता राँची में 1 से 4 मार्च, 2022 तक होगी।
- इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिये प्रतिभागी बालक/बालिका की उम्र सीमा 10 से 12 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। ज़िलास्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 बालक एवं 20 बालिका का चयन किया जाएगा। ये राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
- राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले चयनित बच्चों को मेडिकल परीक्षण से गुज़रना होगा। उसके बाद आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में रिक्ति के अनुसार प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा।
- प्रतिभा चयन प्रतियोगिता में प्रशिक्षुओं का चयन बैटरी टेस्ट (NSTC), नॉर्म्स के आधार पर होगा। इस टेस्ट के ज़रिये प्रशिक्षुओं का शारीरिक वज़न अधिकतम 35 किलोग्राम, ऊँचाई अधिकतम 124 से 153 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षु 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, 6'10 मीटर शटल रन, बॉल थ्रो, वर्टिकल जम्प और 800 मीटर दौड़ में शामिल होंगे।

जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की नई सूची जारी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड सरकार ने ज़िलास्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिये जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की नई सूची जारी की।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही ज़िलास्तरीय नियुक्तियों के लिये जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से संबधित 24 दिसंबर को जारी अधिसूचना को विलोपित कर दिया गया है। इससे पहले क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में उर्दू को शामिल किया गया था।
- क्षेत्रीय भाषाओं की नई सूची में बोकारो से भोजपुरी एवं धनबाद से भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया है।
- जेएसएससी द्वारा मैट्रिक व इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में ज़िलास्तरीय पदों के लिये भाषाओं को ज़िलावार चिह्नित करते हुए यह सूची जारी की गई है।
- उल्लेखनीय है कि विभिन्न संगठनों द्वारा, खासकर बोकारो और धनबाद में भोजपुरी एवं मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किये जाने के विरोध में आंदोलन किया गया था। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो सहित झामुमो के कई नेताओं और कई संगठनों ने सरकार से क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाने की मांग की थी।

एकीकृत कृषि प्रणाली में पशुधन को शामिल करना अत्यंत उपयोगी

चर्चा में क्यों ?

- 21 फरवरी, 2022 झारखंड में राँची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी द्वारा आयोजित 21 दिवसीय राष्ट्रीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के समापन पर किसानों के लिये एक विचार मंथन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने गाय, भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गीपालन, मछली और बत्तखपालन गतिविधियों जैसे पशुधन को एकीकृत खेती में शामिल करने पर ज़ोर दिया।

प्रमुख बिंदु

- बीएयू के कुलपति ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि पशुधन की नवीनतम तकनीकों को शामिल करते हुए कृषि प्रणाली में प्रबंधन, किसानों की आय दोगुनी करने का एक बेहतर विकल्प है, जिससे देश में छोटे और सीमांत किसानों की बेहतर आजीविका और पोषण सुरक्षा मज़बूत होगी।
- गौरतलब है कि लगभग 60 एकीकृत कृषि प्रणालियों की पहचान की गई है और पूरे देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिये सिंचित एवं गैर-सिंचित परिस्थितियों के अनुरूप विकसित की गई हैं।
- शोध में वैज्ञानिकों ने एकीकृत कृषि प्रणाली को देश के किसानों की आय बढ़ाने का सबसे उपयुक्त माध्यम पाया है।
- एकीकृत कृषि प्रणाली एक संपूर्ण कृषि प्रबंधन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य अधिक टिकाऊ कृषि प्रदान करना है। यह कृषि प्रणालियों में पशुधन और फसल उत्पादन का एकीकृत करती है।
- एकीकृत कृषि प्रणालियों ने पशुधन, जलीय कृषि, बागवानी, कृषि-उद्योग और संबद्ध गतिविधियों की पारंपरिक खेती में क्रांति ला दी है। इस प्रणाली में आधार के रूप में फसल गतिविधि के साथ अन्य उद्योगों के अंतर-संबंधित सेट शामिल हैं, इसमें एक घटक से 'अपशिष्ट' सिस्टम के दूसरे भाग के लिये एक इनपुट बन जाता है, जिससे लागत कम हो जाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है एवं उत्पादन और आय में वृद्धि होती है।

दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

चर्चा में क्यों ?

- 24 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी से संबद्ध पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के आंचलिक महायोजना का निर्माण M/s XLRI, Jamshedpur से मनोनयन के आधार पर कराए जाने हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 एवं नियम 235 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

- जमशेदपुर स्थित दलमा वन्यजीव अभयारण्य (आश्रयणी) हाथियों के लिये प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में भौंकने वाले हिरण, सुस्त भालू और विभिन्न सरीसृप प्रजातियाँ उल्लेखनीय हैं।
- 193.22 वर्ग किमी. क्षेत्रफल वाला यह वन्यजीव अभयारण्य सुवर्णरेखा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है।
- यहाँ मुख्यत: शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनमें कुछ शुष्क प्रायद्वीपीय साल हैं। यहाँ की मुख्य वृक्ष प्रजातियों में टर्मिनलिया, जामुन, धौरा, केंदु, करम आदि शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के 10 किमी. के भीतर के क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है।

राज्य में खुला पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- 25 फरवरी, 2022 को झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि भवन में राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिये राज्य के सभी ज़िलों में अटेसटेशन सेंटर के साथ-साथ ऑर्गेनिक उत्पादों को सर्टिफिकेट देने के लिये एक लैब की भी स्थापना की जाएगी।
- राज्य के 58 लाख बिरसा किसानों को जैविक कृषि से जोड़ा जाएगा। जल्द ही इन किसानों को यूनिक कार्ड भी दिया जाएगा।

- मंत्री बादल ने कहा कि कई ऐसे जैविक उत्पाद हैं, जिन्हें अगर सर्टिफिकेट मिल जाए तो उन्हें बाज़ार में अच्छी कीमत मिलेगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
- राज्य में विषैले रसायन मुक्त विशुद्ध पद्धति से उगाए गए कृषि उत्पादों की बहुत मांग है। राज्य के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये जैविक उत्पाद विपणन केंद्र मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ से जैविक विधि द्वारा उपजाई गई प्रमाणीकृत सब्जियाँ, दलहन, तिलहन और मसालों आदि का विक्रय किया जा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनगड़ा प्रखंड में ओफाज एवं भारत सरकार के एसएफएसी के सहयोग से जैविक एफपीओ नीम फूल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है।

तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड विनर 'गुनी गाँव'

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में जलशक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किये गए तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट ज़ोन में गुनी गाँव को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- गुनी गाँव झारखंड राज्य की राजधानी राँची से 30 किमी. दूर खूँटी ज़िले के कर्रा प्रखंड में घुंसुली पंचायत में स्थित है।
- गुनी गाँव की इस उपलब्धि का श्रेय झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत संचालित अनेक योजनाओं, जैसे- 'नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना', 'बिरसा हरित ग्राम योजना'आदि को है जिनका उद्देश्य जल का संचय कर भूमि के जल स्तर में बढ़ोतरी कराना, मिटी के कटाव को कम करना, फसलों की सिंचाई के लिये उपयुक्त जल को संग्रह कर रखना आदि है।
- गौरतलब है कि 2018 में जलशक्ति मंत्रालय ने पहला 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार'लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों/संगठनों को प्रेरित करना तथा जल के महत्त्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना है।